

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 35 संख्या: 137

प्रभात

अजमेर, सोमवार 22 दिसम्बर, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

‘संघ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए काम करता है पर मुस्लिम विरोधी नहीं है’

सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ को भाजपा के नज़रिए से समझना गलत है

कोलकाता, 21 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संगठन का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है और इसे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए।

भागवत ने संघ के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में कोलकाता में आरएसएस 1०० व्याख्यान माला कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, कहा कि आरएसएस को संकीर्ण या तुलनात्मक ढाँचों से नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर आप संघ को समझना चाहते हैं, तो इसका अनुभव करना पड़ेगा। तुलना करने से गलतफहमी होगी। अगर आप संघ को सिर्फ एक और सेवा संगठन मानते हैं, तो आप गलत है।”

भागवत ने कहा, “बहुत से लोगों की प्रवृत्ति संघ को भाजपा के नज़रिए से समझने की होती है, जो बहुत बड़ी

- कोलकाता में आरएसएस के शताब्दी समारोह में व्याख्यान देते हुए भागवत ने कहा कि संघ का मुख्य उद्देश्य नैतिक रूप से ईमानदार और गुणी व्यक्तियों का निर्माण करना है, जो सेवा, मूल्यों व राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित हों व देश के विकास में योगदान दें।

गलती है।” उन्होंने कहा कि हालांकि भाजपा के कई नेताओं की जड़ें आरएसएस में हो सकती हैं, लेकिन दोनों अलग-अलग भूमिकाओं वाले अलग-अलग संगठन हैं। बाद में कोलकाता के साईंस सिटी ऑडिटोरियम में एक अन्य कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आरएसएस राजनीति नहीं करता है और उसका कोई दुश्मन नहीं है।

उन्होंने कहा कि यह संगठन पूरी तरह से हिंदू समाज की भलाई, सुरक्षा और एकता के लिए काम करता है। उन्होंने कहा, “संघ को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोग इसका नाम जानते हैं लेकिन इसके काम को

नहीं समझते। आरएसएस दुश्मनी या टकराव की मानसिकता से काम नहीं करता।” संघ प्रमुख ने कहा कि आरएसएस का मुख्य उद्देश्य सच्जन यानी नैतिक रूप से ईमानदार और गुणी व्यक्तियों का निर्माण करना है जो सेवा, मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव से प्रेरित हों और जो देश के विकास में योगदान दें।

भागवत ने कहा कि संगठन के विकास से कुछ लोगों के हिंत्ों पर असर पड़ सकता है, जिससे विरोध हो सकता है, लेकिन संघ खुद किसी को दुश्मन नहीं मानता। आरएसएस के मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज करते हुए भागवत ने कहा कि ऐसी धारणाएं

तथ्यों के बजाय कहानियों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि संघ का काम पारदर्शी है और कोई भी इसे देख सकता है। उन्होंने कहा, “जो लोग आए हैं और हमारे काम को देखा है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि हम कट्टर राष्ट्रवादी हैं जो हिंदुओं को सुरक्षा के लिए काम करते हैं लेकिन मुस्लिम विरोधी नहीं हैं।” उन्होंने आलोचकों से संगठन का दौरा करने और इसे सीधे समझने का आग्रह किया।

इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के अंदर ज़्यादा एकता और भूली हुई सांस्कृतिक तथा सामाजिक जड़ों की ओर लौटने का आ न किया। बंगाल की विरासत का ज़िक्र करते हुए भागवत ने स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी हस्तियों को याद किया। उन्होंने सामाजिक सुधार में उनकी भूमिका के लिए राजा राम मोहन रॉय की खास तौर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मनरेगा से गांधी का नाम हटाना, उनकी दूसरी हत्या है- चिदंबरम

वरिष्ठ कांग्रेस नेता चिदंबरम ने कहा कि इस विधेयक से ग्रामीण रोजगार की गारंटी कमज़ोर हो गई

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से गांधी का नाम हटाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इसे महात्मा गांधी की दूसरी हत्या करार दिया है। उन्होंने कहा कि संसद से पारित नए कानून के जरिए न सिर्फ गांधी की स्मृति को मिटाने की कोशिश की गई है, बल्कि ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर भी सीधा प्रहार हुआ है। चिदंबरम ने कहा कि 18 दिसंबर को संसद ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी विधेयक पारित किया, जो 2० साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह बदलाव बिना पर्याप्त चर्चा के किया गया और इससे ग्रामीण रोजगार की कानूनी गारंटी कमजोर हो गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी इस कानून का लगातार विरोध करेगी। हालांकि आज ही यानी रविवार को राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूर भी कर

- पी. चिदंबरम ने कहा कि गांधी और नेहरू को सरकारी आदेशों से नहीं मिटाया जा सकता, वे देश की चेतना में बुद्ध और यीशू की तरह जीवित हैं।

दिया है।

चिदंबरम ने कहा कि महात्मा गांधी की पहली हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी और अब उनकी स्मृति को फिर से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू को सरकारी आदेशों से नहीं मिटाया जा सकता, वे देश की चेतना में बुद्ध और यीशू की तरह जीवित हैं।

चिदंबरम ने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित अधिकार था। अगर कोई काम मांगता था तो सरकार कानूनी रूप से उसे काम देने के लिए बाध्य थी। नए कानून में यह अधिकार खत्म हो गया है और अब सरकार की मर्जी से काम दिया जाएगा। इससे ग्रामीण गरीब, दिहाड़ी मजदूर और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी।

चिदंबरम ने नए कार्यक्रम के नाम

पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए हिंदी नाम दक्षिण भारत के ग्रामीणों के लिए समझना मुश्किल है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह योजना पूरे देश में लागू नहीं होगी, बल्कि केवल केंद्र द्वारा तय किए गए जिलों तक सीमित रह जाएगा।

पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि पहले केंद्र सरकार मजदूरी का पूरा खर्च उठाती थी और सामग्री लागत का 75 प्रतिशत देती थी। नए कानून में राज्यों पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। बजट आवंटन लगातार घट रहा है। चार साल पहले जहां 1.11 लाख करोड़ रुपये थे, अब यह 65 हजार करोड़ तक आ गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर राज्यों के पास पैसा नहीं हुआ तो योजना जमीन पर लागू ही नहीं हो पाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण रविवार को 400 से अधिक

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रविवार सुबह भी वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर श्रेणी में बना रहा। शहर के कई प्रमुख इलाकों में सुबह के समय एक्यूआई

- शनिवार को कई इलाकों में एक्यूआई 500 से अधिक हो गया था।

400 के पार दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, अक्षरधाम, आईटीओ, गाजीपुर और आनंद विहार इलाकों में एक्यूआई 438 दर्ज हुआ।

बारापुला फ्लाईओवर पर एक्यूआई 382 और धौला कुआँ पर 397 रहा, जो दोनों बहुत खराब श्रेणी में आते हैं। शनिवार की तुलना में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत शृंखलाओं में से एक, अरावली पर्वत शृंखला इन दिनों खूब चर्चा में है। रविवार को केन्द्र सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज किया,जिनमें कहा गया था कि अरावली की परिभाषा बदल दी गई है ताकि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति दी जा सके। सरकार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस क्षेत्र में नए खनन लौज पर रोक लगाई हुई है। मामले में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

नहीं मिली, इसलिए पर्वत शृंखलाओं में से एक, अरावली क्षेत्र का 9० प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा सुरक्षित क्षेत्र में आएगा। ज्ञातव्य है कि बीते दिनों इन पर्वतों के पास खनन की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई। इस पर केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक जवाब दाखिल किया। इसी जवाब के बाद से देशभर में कुछ

ऐसे घटनाक्रम हुए हैं, जिन्हें लेकर अरावली शृंखला चर्चा के केंद्र में आ गई। इतना ही नहीं अरावली के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर “सेव अरावली कैपेन” यानी अरावली बचाओ अभियान चल पड़ा है।

मामले में सरकार ने साफ किया कि अरावली की परिभाषा राज्यों में प्रमाणित की गई है ताकि किसी प्रकार का गलत इस्तेमाल न हो। इससे पहले, अलग-अलग राज्य खनन की अनुमति देते समय अलग-अलग नियम अपनाते थे।सरकार के अनुसार, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में कानूनी खनन बहुत ही छोटे हिस्से में होता है, केवल

- केन्द्र सरकार ने कहा कि अरावली के लिए असली खतरा अवैध व अनियंत्रित खनन है। इसे रोकने के लिए कड़ी निगरानी, प्रवर्तन तथा ड्रोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल की सिफारिश की है।

०.19 प्रतिशत। दिल्ली में खनन की अनुमति नहीं है। केंद्र ने बताया कि अरावली के लिए असली खतरा अवैध और अनियंत्रित खनन है। इसे रोकने के लिए समिति ने कड़ी निगरानी, प्रवर्तन और ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2०24 में एक समिति बनाई थी, जिसमें राजस्थान,

राष्ट्रपति ने वीबी-जी राम जी विधेयक को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने रविवार को ग्रामीण रोजगार नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव वाले विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) : वीबी-जी राम जी विधेयक 2०25 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों के लिए प्रति वित्तीय वर्ष मजदूरी रोजगार

- यह अधिनियम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के मजदूरी रोज़गार की गारंटी प्रदान करता है, बशर्ते परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों।

की वैधानिक गारंटी को 125 दिनों तक बढ़ाता है और सशक्तिकरण, समावेशी विकास, योजनाओं के अधिसरण (कन्वर्जेंस) तथा परिपूर्ण तरीके से सेवा-प्रदाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, जिससे समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की नींव मजबूत होगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय सांख्यिकी संस्थान पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ा- राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षा संस्थान विचारधारा से नहीं ज्ञान-विज्ञान से चलने चाहिए

नई दिल्ली, 21 दिसंबर। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) पर धीरे-धीरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का संस्थागत प्रभाव बढ़ रहा है। उनका कहना था कि शिक्षा संस्थान किसी विचारधारा से नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान से चलने चाहिए। राहुल गांधी ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आईएसआई के छात्रों से हुई मुलाकात का एक वीडियो अपने वाट्सऐप पर साझा किया।

ज्ञातव्य है कि यह बातचीत संसद परिसर में उनके ‘जन संसद’ कार्यक्रम के तहत हुई थी, जिसमें वे अलग-अलग वर्ग के लोगों से मिलते हैं। राहुल गांधी ने बताया कि आईएसआई के छात्रों ने वही चिंताएं जताईं, जो देश के दूसरे

- कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान आईएसआई के छात्रों ने उनसे मुलाकात यह चिंता जताई थी कि अकादमिक फैसलों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है।

शिक्षण संस्थानों के छात्र और शिक्षक पहले से उठते आ रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आईएसआई में अब अकादमिक फैसलों में आरएसएस का दखल बढ़ रहा है।

इस दौरान राहुल गांधी ने इस बात पर भी जोर दिया कि आईएसआई कोई साधारण संस्थान नहीं है। यह संस्थान ऑनबूट, गणित, अर्थशास्त्र, डेटा साईंस, कंप्यूटर साईंस और नीति निर्माण जैसे क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शोध करता है और देश को विश्वस्तरीय विशेषज्ञ देता रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिन अकादमिक परिषदों को शिक्षाविदों द्वारा चलाया जाना चाहिए, वहां अब नीकरशाही और विचारधारा का हस्तक्षेप हो रहा है। उन्होंने कहा कि

भी हालत में होने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को आज़ादी चाहिए और देश के संस्थान ज्ञान, विज्ञान और स्वतंत्र सोच से चलने चाहिए, न कि किसी भी विचारधारा से।

हरियाणा की सायबर क्राइम थाना टीम रिश्तत की राशि के साथ पकड़ी गई

जयपुर, 21 दिसम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एससीबी) की अजमेर टीम ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना साइबर क्राइम सिरसा, हरियाणा, के उपनिरीक्षक सुरेन्द्र कुमार एवं पुलिस स्टाफ के अन्य सदस्यों को छह लाख रुपये की अवैध राशि सहित पकड़ा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि

- भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने कुचामन सिटी में चैकिंग के दौरान हरियाणा के उपनिरीक्षक व पुलिस स्टाफ को 6 लाख रूपए की अवैध नकदी के साथ पकड़ा।

की भूमि पर रोक लागू होगी। गौरतलब है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को मान्यता दी। इसके अनुसार, कोर और अविनाशी क्षेत्रों, संरक्षित क्षेत्रों, इको-सेंसिटिव जोन, टाइगर रिजर्व, नेटलैंड्स सहित पहाड़ी क्षेत्रों में नई खनन लौज तब तक नहीं दी जाएगी जब तक भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती।

ब्यूरो में गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई कि हरियाणा पुलिस का स्टाफ हरियाणा में दर्ज साइबर क्राइम के मुकदमे के अनुसंधान एवं आरोपियों की तलाश के लिए आया हुआ है। एवं प्रकरण में संदिग्ध लोगों को डरा धमकाकर अवैध रूप से रिश्तत राशि प्राप्त कर वाहन संख्या एचआर 24 जीवी 2222 से हरियाणा जा रहा है।

एससीबी अजमेर की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना भाटी के नेतृत्व में तुरन्त कार्यवाही करते हुये जिला डीडवाना-कुचामन में पुलिस थाना कुचामन सिटी के क्षेत्र त्रिशिंगिया में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

●

●

●

●

⊕

●

●

●

●

⊕

●

●

●

●

⊕

●

●

●

●

CMYK